an>

Title: Need to depute private school teachers as well as unemployed youth in census, election duties and other public welfare programmes.

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली)ः उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक राज्यों में अनेक शासकीय कार्य, जैसे- जनगणना, मतदाता सूची का निर्धारण, पुनरीक्षण, सहकारिता, पंचायत तथा विभिन्न प्रकार के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, सरकार के विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रमों में सामान्य तौर पर और स्वाभाविक रूप से प्राथमिक एवं जूनियर (उच्च माध्यमिक) प्राध्यापकों की ड्यूटी लगातार लगायी जाती है। इसके कारण देश में प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के अध्ययन-अध्यापन एवं गुणवत्ता पर बहुत ही कुप्रभाव पड़ता है। संबंधित अध्यापकगण अध्यापन की जगह वर्ष के छः माह लगभग इन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं, जिससे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में सामान्य, मध्यम आय एवं गरीब तबके के बच्चों का शैक्षणिक विकास प्रभावित होता है।

अतः इस विषय में मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि ऐसी नीति बनायी जाये, जिससे इनके कार्यों में निजी विद्यालयों के अध्यापकों को भी लगाया जाये और साथ-साथ पंजीकृत बेरोजगार नौजवानों को भी उचित प्रशिक्षण देकर इस कार्य के लिए विशेष रूप से अलग से रजिस्ट्रेशन कराया जाये। इन्हें इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक एवं उत्कृष्ट कार्य के लिए समुचित पुरस्कार भी दिये जायें, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में साक्षरता एवं शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़े तथा एक नये प्रकार के युवाओं एवं कर्मियों की टीम भी तैयार हो, जिससे उन्हें रोजगार के नये अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।